

## ‘बैंक्स बोर्ड ब्यूरो’ की कार्यक्षमता पर सवाल

### चर्चा में क्यों?

हम जानते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र में अभी भी सरकारी बैंकों का दबदबा है। दरअसल, सरकारी बैंक होने का फायदा यह है कि उन्हें सरकार द्वारा गैर-नष्पिपादनकारी परसिंपत्तियों (एनपीए) से नपिटने हेतु कयि जा रहे परयासों का सर्वाधकि लाभ मलिता है, लेकनि सच्चाई यह है कि सरकारी बैंकों को कोई राहत नहीं मलिी है। गौरतलब है कि बैंकों के ढाँचे में सुधार लाने और उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापति ‘बैंक्स बोर्ड ब्यूरो’ (Banks Board Bureau) ने भी उम्मीद के मुताबकि प्रदर्शन नहीं कयिा है।

### क्या है ‘बैंक्स बोर्ड ब्यूरो’ ?

- फरवरी 2016 में सरकार ने ‘बैंक्स बोर्ड ब्यूरो’ का गठन कयिा और उसे सरकारी बैंकों एवं वत्तितीय संस्थानों में शीर्ष पदों के लयि उम्मीदवार तय करने की ज़मिमेदारी दी गई।
- बाद में सरकार ने बैंकों के लयि पूंजी जुटाने की योजना तैयार करने के अलावा व्यावसायकि रणनीति तैयार करने का दायतिव भी ‘बैंक्स बोर्ड ब्यूरो’ को सौंप दयिा। पूर्व नयित्त्रक महालेखापरीक्षक वनिोद राय को इसका अध्यक्ष बनाया गया था।

### ‘बैंक्स बोर्ड ब्यूरो’ से संबंधति समस्याएँ

- ‘बैंक्स बोर्ड ब्यूरो’ पी. जे. नायक समतििकी अनुशंसाओं के क्रयिान्वयन का आधा-अधूरा कदम था। नायक समतििकी मुख्य अनुशंसा यह थी एक ऐसी होल्डिंग कंपनी को आगे लाया जाए जो बैंकों के रोजमर्रा के प्रशासन और नयिमन में सरकार की भूमकिा कम कर सके।
- इस दशिा में पहले कदम के रूप में बैंक बोर्ड ब्यूरो के गठन का सुझाव आया, लेकनि जब ब्यूरो का गठन हुआ तो उसे कोई अधकिार नहीं दयिा गया।
- नायक समतिि ने सुझाव दयिा था कि इसे बोर्ड स्तर की नयिुक्तयिाँ समेत सभी वरषिठ नयिुक्तयिाँ की नगिरानी करनी चाहयि, लेकनि इसे इस कदर सीमति कर दयिा गया कि यह केवल सरकारी बैंकों और वत्तितीय संस्थानों के प्रमुखों के नाम सुझाने के ही काम आ सका।
- इससे आईआईएफसीएल, आईएफसीआई, सडिबी और एग्जमि बैंक जैसे संस्थानों के प्रमुखों के चयन का अधकिार छीनकर वत्ति बैंक को दे दयिा गया।

### नष्पिकर्ष

- ‘बैंक्स’ बोर्ड ब्यूरो को सरकारी बैंकों के शासन-प्रशासन के मानकों को सुधारने का काम सौंपा गया था।
- यदइसे सच में समुचति अधकिार प्रदान कयि गए होते तो यह सरकारी बैंकों की स्वायत्तता में सुधार लाने वाला एक बड़ा कदम हो सकता था।
- इससे बैंकों की क्षमता में भी सुधार देखने को मलि सकता था। हालाँकि ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया।
- बहरहाल, अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि यह ब्यूरो मोटे तौर पर एक अप्रभावी नकिया है और सार्वजनकि बैंकों की स्वायत्तता बढ़ाने की दशिा में इसके द्वारा कोई अन्य महत्त्वपूर्ण परयास नहीं कयिा जा रहा है।
- ऐसे में सरकार को या तो ‘बैंक्स बोर्ड ब्यूरो’ में सुधारों का उचति खाका पेश करना चाहयि या फरि इसे बंद कर देना चाहयि।